

second project, additional assistance of Rs. 33.309 crores has been given to State Government for the period ending 31st March, 1984, on the basis of credits disbursed.

(c) In view of the above, the question does not arise.

Measures to Plug Loopholes in Delhi Stock Exchange

3058. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it has come to the notice of Government that a stock exchange broker has cheated the Delhi Stock Exchange of about Rs. 30 lakhs ;

(b) if so, the details of the case ;

(c) the action taken against the persons involved in the fraud ; and

(d) measures taken to plug the loopholes so that such frauds and cheatings do not take place in future ?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) and (b). According to the information supplied by the Delhi Stock Exchange Association Ltd., recently, Shri Sardari Lai Mehra, a member of the Delhi Stock Exchange failed to meet his obligations in respect of payment of Rs. 6,94,015.50 on account of delivery of shares and certain differences arising out of the closed transactions. The Stock Exchange has also received complaints from a number of other members of the Stock Exchange from whom delivery of shares was taken by the aforesaid member against issue of bank debit notes or cheques to the extent of over Rs. 11 lakhs which have not been honoured for want of funds in his account. Further, the Exchange has also received complaints from various investors regarding non-payment of money by the said broker against sale of shares or non-delivery of shares against the payments made to the extent of about Rs. 10 lakhs.

(c) and (d). The Delhi Stock Exchange has informed that relevant Bye-laws and Regulations in regard to settlement of

bargains in non-cleared securities are being strictly enforced. Shri Sardari Lai Mehra has been declared a defaulter under Bye-law 308 of the Delhi Stock Exchange by the Board of Directors of the Exchange in the meeting held on 9th July, 1984.

मंत्रालय में नई सामान्य भतियां

3059. श्री निहाल सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1983 से सभी सरकारी सेवाओं में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया था चाहे वे स्थायी हों अथवा दैनिक मंजूरी पर ;

(ख) क्या इस प्रतिबन्ध के बावजूद कई विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नई भर्ती की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और नई आम भर्ती कब तक की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) से (ग) मुद्रा-स्फीति-निवारक उपार्यों के एक भाग के रूप में 3 जनवरी, 1984 को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया गया था कि केवल ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले ही भर्ती की कार्यवाही की जा चुकी थी, वर्तमान रिक्तियों को 30-9-1984 तक न भरें। अनुकम्पा के आधार पर भर्ती या बिकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति, फालतू कर्मचारियों को फिर से लगाने, वर्ग "ब" रिक्तियों पर अनियमित भ्रमियों को नियमित करने, भर्ती नियमों के अनुसार विशुद्ध रूप से पदोन्नति द्वारा पदों के भरे जाने, वशातें कि प्रतिबन्ध आदेशों की अवधि के दौरान संवर्ग के निम्नतम स्तर में इनकी परिणामी रिक्ति को न भरा जाए, के मामलों में भी प्रतिबन्ध से छूट दी गई है। ये प्रतिबन्ध आदेश प्रतिनियुक्ति की अवधि के आधार पर ग्रहण किए गए पदों के मामलों में पदधारियों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुई रिक्तियों को भरने तथा भर्ती